

प्रेषक,

मनीष मिश्र,  
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2013

**विषय:** जिला हरिद्वार में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रिक्त पद पर आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2681/न्या०अनु०/जि०शा०अधि०/2011-13 दिनांक 16-12-2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला हरिद्वार के फौजदारी न्यायालयों के समक्ष पैरवी/प्रतिवाद करने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री इन्द्रपाल बेदी, अधिवक्ता, जिला हरिद्वार को जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर शासनादेश संख्या-214/XXXVI (1)/2011-7 चार/2005 दिनांक 11 नवम्बर, 2011 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस दरों पर प्रतिधारक के रूप में आबन्धन-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन 01 वर्ष के लिए आबद्ध किया जाता है। उनका आबन्धन-पत्र एतद् संलग्न है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित अधिवक्ता का आबन्धन-पत्र उन्हें तुरन्त उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित सहमति एवं आयु का प्रमाण-पत्र, अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा उनके आवास का विवरण प्राप्त होने पर शासन को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

3- सम्बन्धित अधिवक्ता, यदि इस समय शपथ-आयुक्त, नामिका वकील, नोटरी या इस प्रकार के अन्य किसी शासकीय पद अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत हो, तो उनसे उक्त पद से त्याग पत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा इसकी सूचना शासन को भी दी जाय।

4- मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि यदि आबन्धित अधिवक्ता लिखित सहमति तथा अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें तो उक्त प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आप न्यायालय का कार्य जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रूप में उक्त अधिवक्ता से प्रारम्भ करा दें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

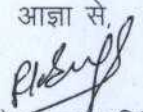
भवदीय,

(मनीष मिश्र)  
अपर सचिव

संख्या: ०7-जा(B)/XXXVI(1)/2013-135 जी०/2001 टी०सी० तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव मा० न्याय मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 2- जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 4- श्री इन्द्रपाल बेदी, अधिवक्ता, जिला न्यायालय परिसर, हरिद्वार
- 5- एन.आई.सी./गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(अनंदा कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव